RNI NO - UPHIN/2022/86937

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी खबर

वर्ष – 04 | अंक – 78 | जौनपुर रविवार, 01 नवम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पीड़ित परिवार ने लगाया राजनीतिक दबाव का आरोप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में पीड़ित परिवार को कथित राजनीतिक दबाव और धमकी के आरोपों के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो से संपर्क करने की सलाह दी है। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और विजय विष्णोई की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने यह दावा किया है कि राज्य के अधिकारियों ने परिवार को धमकाने और मनाने की कोशिश की। अदालत ने कहा याचिकाकर्ता इस मामले में सीबीआई से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल, इस पर किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह हादसा सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है, जिसे गंभीरता से लेना जरूरी है। अदालत ने तमिलनाडु सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह सीबीआई जांच में पूरी तरह सहयोग करे। विज्ञापन बता दें कि 13 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने कहा था कि यह घटना राष्ट्रीय चेतना को झकझोर देने वाली है और इसमें निष्पक्ष जांच जरूरी है। कोर्ट ने अभिनेता–राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (ज्टड्ढ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति गठित की थी, जिसका नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी कर रहे हैं।

उमर खालिद–शरजील की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान की याचिकाओं पर 3 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखेगा। दिल्ली दंगे में गहरी साजिश मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उमर खालिद समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगे के मामले में इन सभी की जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे के पीछे गहरी साजिश थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान के साथ ही दिल्ली पुलिस के तर्क सुने। अब सोमवार यानी 3 नवंबर को पीठ याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी। गुलफिशा फातिमा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह बीते पांच वर्षों से जेल में बंद है। और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। सिंघवी ने कहा कि गुलफिशा फातिमा ही अब दिल्ली दंगे के मामले में जेल में बंद है।

पीएम मोदी देंगे 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर (शनिवार) को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, जहाँ वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएंगे। राज्य में रहते हुए, शदिल की बातश कार्यक्रम के तहत, वे नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में शजीवनदानश समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2500 बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके बाद, लगभग 10रू45 बजे, प्रधानमंत्री ब्रह्माकुमारीज के ष्शांति शिखरष का उद्घाटन करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। बयान के अनुसार, लगभग 11रू45 बजे, प्रधानमंत्री नवा रायपुर अटल नगर स्थित

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे, जिसे ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करने और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 1रू30 बजे, प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई–बुक ष्आदि शौर्यष का शुभारंभ करेंगे और स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लगभग 2:30 बजे, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए 14,260 करोड़ से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे।

आधुनिक भारत के शिल्पी थे लौहपुरुष, देश उनका कृतज्ञ रहेगा : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लखनऊ के हजरतगंज के सरदार पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश हमेशा ही उनका ऋणी रहेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर वर्ष उनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी ने कहा कि लौह पुरुष, 'भारत रत्न' सरदार वल्लभ भाई पटेल सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत की एकता जो

हमें आज दिखाई देती है, वह सरदार साहब के कारण ही है। श्रद्धेय पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत आज लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्यशाला में सहभाग कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। 'सरदार / 150 यूनिटी मार्च' हेतु सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि अंग्रेजों की नीति भारत को कई टुकड़ों में बांटने की थी लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा करने से रोकने का काम किया। लौह पुरुष आधुनिक भारत के शिल्पी थे।।

आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बुद्धि–नैतिकता से जीते जाएंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध अब गैर–गतिज और गैर–संपर्क होता जा रहा है और इसलिए इसके लिए ऐसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है जिसके लिए सैन्य शक्ति, बौद्धिक कौशल और नैतिक तैयारी की आवश्यकता हो। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि युद्ध के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अब ये आमने सामने नहीं लड़े जाते, इसलिए इनका सामना करने के लिए

सैन्य शक्ति, बौद्धिक क्षमता और न्यायसंगत तैयारी की आवश्यकता है। सेना प्रमुख ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को थिंक टैंक, प्रयोगशालाओं और युद्धक्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने भी सेना और रक्षा थिंक टैंक 'सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज' द्वारा आयोजित 'चाणक्य डिफेंस डायलॉगरू यंग लीडर्स फोरम' में सैन्य अधिकारियों, छात्रों और रक्षा विशेषज्ञों को संबोधित किया। सेना प्रमुख ने अपने भाषण में युद्ध की बदलती प्रकृति और इस परिदृश्य में आवश्यक तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ''युद्ध में भाग–दौड़ अब नहीं होती और यह संपर्क–रहित होता जा रहा है'' और इसलिए इसका सामना करने के लिए सैन्य शक्ति, बौद्धिक कौशल और न्यायसंगत तैयारी की आवश्यकता है।'' ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग में शामिल होती रहीं कर्नल सोफिया कुरैशी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं।

धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने पूरा किया सरदार पटेल का अधूरा संकल्प - अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल को तत्कालीन कांग्रेस सरकार से वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पहले गृह मंत्री को 41 साल की देरी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, केंद्रीय गृह मंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना और सरदार पटेल के सम्मान में एक भव्य स्मारक के निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। शाह ने कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल को पर्याप्त

सम्मान नहीं दिया। सरदार पटेल को 41 साल की देरी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया...देश में कहीं भी न तो कोई स्मारक बनाया गया और न ही कोई स्मारक...जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तभी उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना की और सरदार पटेल के सम्मान में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया। इससे पहले आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के पहले गृह मंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने सरदार पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि आधुनिक भारत पटेल की दूरदर्शिता और प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर सरदार पटेल के संकल्प को पूरा किया है। शाह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेजों ने देश को 562 रियासतों में विभाजित करके छोड़ने का फैसला किया.।

फिल्मी दुनिया से राजनीतिक शिखर तक, बिहार की सियासत के धुरंधर बने चिराग पासवान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। फिल्मी दुनिया से अपने सफर की शुरूआत करने वाले चिराग पासवान अब अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। आज यानी की 31 अक्तूबर को चिराग पासवान अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि बिहार के सियासी पटल पर तेजी से उभरते राजनेताओं में चिराग पासवान का नाम शामिल है। उन्होंने बहुत कम समय में राजनीतिक गलियारों में अपनी पहचान बनाई है। चिराग पासवान की सियासत को सिर्फ इस बल पर नहीं आंका जा सकता है, कि वह रामविलास पासवान के पुत्र

हैं। बल्कि उन्होंने राजनीति में अपनी योग्यता को कई बार साबित कर दिखाया है। वह वर्तमान समय में बिहार की सियासत के प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में.. दिल्ली में 31 अक्तूबर 1982 को चिराग पासवान का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामविलास पासवान था, जोकि राजनीति का बड़ा नाम थे। चिराग ने अपनी शुरूआती शिक्षा दिल्ली से पूरी की और फिर यहीं से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। चिराग पासवान फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनेता की भूमिका भी निभाई, लेकिन फिल्मी दुनिया में चिराग को कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। साल 2011 में चिराग पासवान ने अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया था।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज वाराणसी दौरे पर, सत्रम भवन का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एक दिवसीय दौरा करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा–अर्चना करेंगे। एक अधिकारी ने एक बयान में बताया कि इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी के सिगरा में नए सत्रम भवन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ज्यादा जानें क्षेत्रीय समाचार ऐप क्रिकेट टूर्नामेंट टिकट खेल जगत अपडेट साक्षात्कार प्रशिक्षण खेल समाचार सदस्यता शीर्ष रुझान समाचार समाचार विश्लेषण पाठ्यक्रम विविध लेख दैनिक समाचार पत्र छठ महापर्व सामग्री नेतृत्व और देशभक्ति को किया याद, बताया प्रेरणा का स्रोत श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी ने 60 करोड़ रुपए की लागत से 140 कमरों वाले 10 मंजिला सत्रम का निर्माण किया है। यह सोसाइटी द्वारा वाराणसी में निर्मित दूसरा सत्रम है, और इसका उद्देश्य आने वाले श्रद्धालुओं

की सेवा के साथ–साथ युवा पीढ़ी को इस पवित्र शहर की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधन को दर्शाती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में काशी–तमिल के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। एनडीए ने साझा घोषणा पत्र किया जारी उद्घाटन के बाद उपराष्ट्रपति काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और पूजा–अर्चना करेंगे। इससे पहले राधाकृष्णन ने कोयंबटूर, तिरुप्पुर, मदुरै और रामनाथपुरम में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद गुरुवार को अपनी तमिलनाडु यात्रा संपन्न की। यह यात्रा 28 से 30 अक्टूबर तक चली।

किसानों की कर्जमाफी के लिए उच्चाधिकार समिति गठित

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। किसानों की कर्जमाफी को लेकर सरकार ने उच्चाधिकार समिति गठित करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग से नहीं था कोई संबंध महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह निर्णय किसान नेता और विधायक बच्चू कडू के हालिया आंदोलन के बाद लिया गया है। किसान नेता के आंदोलन को देखते हुए, जिसके चलते सरकार

को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार और मित्रा समूह के सीईओ प्रवीण परदेशी होंगे। साथ ही, समिति में कुल 9 सदस्य होंगे, जिनमें महसूल, वित्त, कृषि, सहकार और विपणन विभागों के अपर मुख्य सचिव, साथ ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। स्कूल कॉन्ट्रैक्ट के 2 करोड़ बकाया पर रोहित आर्या ने उठाया जानलेवा कदम सरकार ने समिति को 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। यह समिति किसानों की कर्जमुक्ति के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन सिफारिशें तैयार करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कई जिलों में किसान सड़क पर उतर गए हैं और ट्रैक्टर मार्च के जरिए वे सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस आंदोलन की अगुवाई बच्चू कडू कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में शुरू हुआ यह मार्च अब पूरे राज्य में फैल चुका है। आंदोलन कर रहे किसानों की प्रमुख मांग में एमएसपी की गारंटी और कर्जमाफी शामिल है।

लौह पुरुष की जयंती पर कांग्रेस ने भाजपा-आरएसएस पर साधा निशाना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि उनके निस्वार्थ नेता भी हैरान हो जाते, अगर उन्हें पता चलता कि उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद पटेल के शब्दों में, इस विचारधारा ने ऐसा माहौल बनाया, जिससे महात्मा गांधी की हत्या जैसी खौफनाक घटना संभव हो सकी। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश कहा, खासकर 2014 से दो लोगों का समूह (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) और उनका तंत्र 2014 से इतिहास को बेधड़क तोड़– मरोड़कर पेश कर रहा है। रमेश ने एक्स पर लिखा, आज जब कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल

की 150वीं जयंती मना रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि 13 फरवरी 1949 को जवाहर लाल नेहरू ने गोधरा में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया था, जहां उन्होंने अपना वकालत का करियर शुरू किया था। इस अवर नेहरू का भाषण दोबारा पढ़ना चाहिए, ताकि उनकी तीन दशकों से अधिक की मजबूत और गहरी साझेदारी को समझा जा सके। रमेश ने कहा, सरदार पटेल की 75वीं जयंती के मौके पर नेहरू ने कहा था कि पटेल ने अपने लंबे और उल्लेखनीय सेवा रिकॉर्ड के बावजूद देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला और उन्होंने राष्ट्रीय गतिविधियों में उनके साथ तीस वर्षों का साथ साझा किया। इन वर्षों में उठापटक और बड़ी घटनाओं के बीच पटेल एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे, जिनसे बड़ी संख्या में लोग मार्गदर्शन की उम्मीद रखते थे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 19 सितंबर 1963 को तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने संसद भवन और चुनाव आयोग कार्यालय के पास नई दिल्ली के प्रमुख गोल चौराहे पर सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया था। नेहरू भी उस समय मौजूद थे और उन्होंने मूर्ति पर श्भारत की एकता के शिल्पकारश का सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द चुना। उन्होंने याद दिलाया कि 31 अक्तूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की शताब्दी वर्ष समापन समारोह की अध्यक्षता की और उनकी अनेक उपलब्धियों और योगदानों को व्यापक रूप से याद किया। रमेश ने कहा, 2014 से खासकर, इतिहास दो लोगों के समूह (जी2) और उनके तंत्र द्वारा बेधड़क विकृत और गलत पेश किया जा रहा है।

संपादकीय

शाब्दिक गिरावट वाला एक और चुनाव

सुशासन, स्वच्छता और शुचिता के दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास शाब्दिक सभ्यता का घोर अभाव दिख रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेन्द्र मोदी चुनाव आते ही सारे चोले उतारकर केवल भाजपा के स्टार प्रचारक बन जाते हैं और फिर चुनाव जीतने के लिए भाषा का स्तर चाहे जितना गिराना हो, उस स्तर पर उतरने में जरा भी नहीं झिझकते है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी बातें, उनके विचार, उनकी भाषा दुनिया के दूसरे कोनों में पहुंचती होगी, तो उनकी कैसी छवि बनती होगी। श्री मोदी को केवल सत्ता में आने और उसे बचाए रखने की परवाह है, उसी के लिए वे अपने विरोधियों पर कीचड़ उछालते रहते हैं। जैसे बिहार की अपनी एक सभा में उन्होंने कहा कि बहनों–बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है। इससे पहले झारखंड चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी भी हड़प रहे हैं। बेशक मोदीजी लड़कियों की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद होंगे, लेकिन ये सरोकार उनकी भाषा में कतई नहीं झलक रहा। लड़कियों को उठा लेना, जैसे निम्नस्तरीय फिकरे किस किस्म के लोग कसते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। केंद्र की 11 साल की सत्ता में रहकर, तमाम केन्द्रीय एजेंसियों का काम करीब से देखकर नरेन्द्र मोदी के पास कांग्रेस पर हमला करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं होगी। पिछली सरकारों की गलतियों की सतर्क व्याख्या करके नरेन्द्र मोदी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को घेर सकते हैं, लेकिन वे इस सघन परिश्रम से बचने के लिए सीधे उन जुमलों पर उतर आते हैं, जिन पर जनता का ध्यान एकदम से चला जाता है। जैसे लोकसभा चुनावों में श्री मोदी ने मंगलसूत्र चुराने की बात कही थी। सावन में मछली–मटन खाने को मुद्दा बनाया था। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर सीधे चारित्रिक लांछन पर उतर आए कि बेटियों को छीन रहे हैं। अब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस को घेरने के लिए नरेन्द्र मोदी इसी पैंतरे को आजमा रहे हैं। आरजेडी के लिए श्री मोदी ने कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन बिहार में राजद के श्जंगलराजश की पहचान है। हालांकि 2005 के बाद से आरजेडी सत्ता में नहीं आई है, महज 17 महीनों के लिए सत्ता में रही तो वह भी जेडीयू के साथ मिलकर। इसलिए बिहार के समाज में क्रूरता, कटुता, कुशासन मोदीजी को नजर आ रहा है, तो इसके लिए उनकी अपनी पार्टी भाजपा और जेडीयू जिम्मेदार माने जाएंगे, जो लगातार सत्ता पर बने हुए हैं। अगर एनडीए सरकार के होने के बावजूद कट्टे का डर श्री मोदी दिखा रहे हैं या करप्शन की बात कर रहे हैं, तो असल में वो खुद पर ही उंगली उठा रहे हैं। बहरहाल, चुनावों में इस तरह की जुमलेबाजी सुनने की जनता अभ्यस्त हो चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री की भाषा का गिरता स्तर अब चर्चा का विषय नहीं बनता है। जबकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं है। वैसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अब पूरी आक्रामकता के साथ नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं। और इसमें उनकी भाषा भी कई जगह खराब नजर आई। राहुल गांधी की भाषा में अशिष्टता दिखी, गनीमत है कि अभद्रता इससे दूर रही। मुजफ्फरपुर में बुधवार को राहुल गांधी ने कहा कि वोट पाने के लिए मोदीजी कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, जनता उन्हें नाचने कहेगी, तो वे नाच भी लेंगे। राहुल गांधी ने यह तंज छठ पूजा को लेकर किया, जिसमें नरेन्द्र मोदी के अर्घ्य देने के लिए यमुना नदी से अलग एक घाट में पाइप से पानी लाकर इंतजाम किया गया था। हालांकि आखिरी वक्त में नरेन्द्र मोदी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया।

अस्पष्ट मुद्दे, अविश्वसनीय नेतृत्व

अरविन्द मोहन

यह आलेख एक मायने में राहुल गांधी की राजनीति के खास चरित्र और बिहार चुनाव की अब तक बनी स्थिति को समझने का प्रयास है। जिस राजनीति में हर चुनावी सभा लाखों–करोड़ों का खर्च मांगती है उसमें भी बिहार में राहुल की ज्यादातर सभाएं बिना धन खर्च की हुईं और जगह–जगह यह स्थिति रही कि उनमें पैर रखने जगह नहीं थी। वोट चोरी के साथ राहुल जिस तरह अति पिछड़ों, दलितों और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। बिहार में मतदान से पहले 12 राज्यों की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का चुनाव आयोग का फैसला सिर्फ प्रशासनिक और रूटीन काम का विस्तार लगने से ज्यादा एक राजनैतिक चुनौती वाला लगता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बिहार के पुनरीक्षण को लेकर हजारों आपत्तियां पड़ी हैं, अदालती आदेश से इस कार्यक्रम में दसियों बदलाव हुए और अदालत की प्रतिकूल टिप्पणियों की संख्या भी अच्छी खासी रही। इन सबके बावजूद और बिना ज्यादा बदलाव के इस काम का विस्तार करना आयोग के आत्मविश्वास से ज्यादा हठधर्मिता लगती है। और जाहिर तौर पर इसको ताकत उसे बिहार में पुनरीक्षण विरोधी अभियान अर्थात कथित वोट चोरी रोकने के आंदोलन की हवा निकालने से मिली है। ठीक ठाक जोर पकडने

के बाद यह अभियान आयोग द्वारा दिखाई जा रही अशिष्टता, भाजपा–जदयू द्वारा उससे चार कदम आगे बढ़ाकर घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाने, अदालत द्वारा कराए गए भूल–सुधार से भी ज्यादा वोट चोरी अभियान के नायक राहुल गांधी के श्गायबश होने और उनके सारथी तेजस्वी यादव द्वारा की गई गलतियों से आज ठंडा पड़ गया है और विपक्ष चुनाव में उलझा हुआ है। इस चुनाव में वोट चोरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं लगता–पलायन, बेरोजगारी और कानून–व्यवस्था(जंगल राज) उससे बड़े मुद्दे लगते हैं और यह तब है जब कर्नाटक में वोट चोरी के मामलों को उससे जुड़े विशेष जांच दल ने सही पाया है। यह आलेख आयोग के मौजूदा फैसले को लेकर नहीं है, जबकि यह फैसला बिहार के वोटरों को कुछ बताने के लिए जरूर है। यह आलेख एक मायने में राहुल गांधी की राजनीति के खास चरित्र और बिहार चुनाव की अब तक बनी स्थिति को समझने का प्रयास है। जिस राजनीति में हर चुनावी सभा लाखों–करोड़ों का खर्च मांगती है उसमें भी बिहार में राहुल की ज्यादातर सभाएं बिना धन खर्च की हुईं और जगह–जगह यह स्थिति रही कि उनमें पैर रखने जगह नहीं थी। वोट चोरी के साथ राहुल जिस तरह अति पिछड़ों, दलितों और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करते थे और जिस दिलेरी से मोदी सरकार के कामकाज की आलोचना करते थे उससे उनके प्रति एक खास सहानुभूति दिखती थी जो बाद में प्रियंका गांधी की रैलियों में भी दिखी। विपक्ष भी घबराया था और उसने राहुल के आगे तेजस्वी के नतमस्तक होने का मसला उठाया और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी उसका लाभ गठबंधन में ज्यादा और अच्छी सीटें हासिल करने का प्रयास करने के रूप में उठाया। लेकिन जब तक यह सब परिणाम निकले तब तक संवादहीनता, टिकट बेचने के आरोप, राहुल–प्रियंका के बिहार मामलों से एकदम हाथ झाड़ लेने और बिहार के प्रभारी अलावरू को किनारे करने तथा लालू–तेजस्वी के आगे सरेंडर करने में जैसी घटनाओं का पूरा क्रम दिख गया। कांग्रेस के टिकट बिके लेकिन अलावरू उसमें शामिल थे यह कम लोग मानते है, फिर भी उनकी विदाई तो हुई ही। टिकट जदयू को छोड़कर हर दल में बिके–उसमें आरोप–प्रत्यारोप चले और महागठबंधन के टिकटों में लालू परिवार का जोर चला। तेजस्वी और राजद की जो स्थिति है उसमें यह स्वाभाविक था। लेकिन तेजस्वी नेता घोषित होने के लिए क्यों बेचैन हुए, पप्पू यादव और कन्हैया जैसों से क्यों चिढ़तेध्डरते हैं और गठबंधन की अगुआई करते हुए क्यों नहीं चीजों को समेटने का काम किया? यह समझना मुश्किल है। अब अगर उनको हर घर में सरकारी नौकरी देने या जीविका दीदियों वगैरह को स्थायी काम देने या बिहार में उद्योग लगाने जैसा कार्यक्रम चुनाव जिताऊ और ज्यादा बढिया लगता है तो उन्होंने राहुल के वोट चोरी कार्यक्रम के समय ही इस मसले को क्यों नहीं उठाया। वे तब तो उनका सारथी बनकर भी निहाल थे। अति पिछड़ों की बात करके टिकट देने में अहीर और कुशवाहा पर जोर देना और मुसलमानों को निराश करना भी समझ न आने वाला फैसला है। सबसे पुराने अखाड़ेबाज लालू यादव की देखरेख के बावजूद यह सब कैसे हुआ समझना मुश्किल है। इस मामले में नीतीश कुमार ने चौंकाया। कमजोर और बीमार होने के शोर के बीच वे पर्याप्त सक्रिय दिखे और उनके यहां सीनियर लोगों को टिकट देने के साथ ही कम से कम हंगामा हुआ। उनके सरकार की उपलब्धियां उनके साथ ही भाजपा और लोजपा के लिए भी सहारा बनी हुई हैं। पिछली बार लोजपा और उसके पीछे खड़ी भाजपा ने उनकी छवि बिगाडने का प्रयास किया था–इस बार आम लोगों में उनके प्रति सहानुभूति होने से लेकर भाजपा और लोजपा में भी उनका ही भरोसा रह जाने का भाव भी दिखता है। प्रशांत किशोर ने भाजपा के पांच शीर्ष नेताओं और उनके दुलारे मंत्री के कारनामे सामने करके उनके नेतृत्व को ज्यादा मजबूत बना दिया है। भाजपा भले उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित न करे लेकिन चुनाव उनके सहारे ही लडना उसकी मजबूरी है। खुद प्रशांत सारी रणनीतिक समझ रखते हुए क्यों घोषणा करके तेजस्वी से लडने नहीं गये यह उनके पूरे अभियान पर भारी पड़ गया। अगर कांग्रेस और महागठबंधन को अब वोट चोरी याद नहीं रहा और चुनाव जिताऊ मुद्दा समझ नहीं आता तो यह मुश्किल भाजपा और एनडीए के लिए और बढ़ी है। नीतीश कुमार शासन के बीस साल की उपलब्धियों की जगह उससे पहले के पंद्रह साल के राजद शासन(जिसे भाजपा जंगल–राज बताती है) को चुनावी मुद्दा बनाने का कितना लाभ होगा कहना मुश्किल है। पिछली बार तक राजद के श्गुंडाराजश का डर दिखाना लाभकर था तो पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी हुआ और उससे भाजपा को लाभ मिला। इस बार अभी तक ध्रुवीकरण के सारे प्रयास हवाई ही लगते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यात्राओं से भी खास लाभ नहीं दिखाता। उनके शासन को लेकर एक प्रशंसा–भाव है लेकिन कटेंगे–बंटेंगे टाइप नारों का असर नहीं लगता। मोदी जी और उनसे भी ज्यादा अमित शाह एक जबरदस्त चुनावी प्रबंधन का नमूना पेश कर रहे हैं लेकिन उससे बिना नेता और बिना मुद्दा वाली भाजपा को लाभ होता नहीं लगता। लेकिन अभी तो चुनाव प्रचार और चुनाव ही असली रंग में कहां थे। अभी तक तो दिवाली–छठ का ही शोर ज्यादा था।

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव में भारत कर रहा ऊर्जा पुनर्संतुलन

के रवींद्रन

इस बदलाव के लिए भारत की लाभ संरचना तात्कालिक नहीं है। हालांकि रूसी कच्चे तेल से दूर जाने से भू–राजनीतिक जोखिम कम होता है, लेकिन इससे मास्को द्वारा दी जाने वाली भारी छूट तक पहुंच भी कम हो जाती है– एक ऐसी छूट जिसने भारत को अपने आयात बिल को कम करने और घरेलू उद्योग के मार्जिन को सहारा देने में मदद की थी। लगता है कि वाशिंगटन के बढ़ते दबाव के चलते नई दिल्ली अपनी कच्चे तेल की सोर्सिंग रणनीति में बदलाव कर रही है, जो मास्को से दूर होकर अमेरिका के साथ गहरे संबंधों की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। पिछले कुछ महीनों में, प्रमुख निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी यूराल क्रूड की नई खरीद बंद कर दी है या रोक दी है, और सरकारी अधिकारी सार्वजनिक रूप से रूस से परे आपूर्ति विकल्पों के विस्तार और अधिक अनुकूल अनुबंध शर्तों की ओर इशारा कर रहे हैं। यह बदलाव भारत में अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ मेल खाता हैरू घरेलू आंकड़े बताते हैं कि इस सप्ताह अमेरिका से आयात की मात्रा लगभग 540,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो 2022 के बाद से दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है। यह अंतर्निहित गतिशीलता अमेरिकी प्रशासन द्वारा ऊर्जा–व्यापार उत्तोलन को एक भू–राजनीतिक साधन के रूप में मुद्रीकृत करने के निर्णय से प्रेरित प्रतीत होती है। वाशिंगटन ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया है, जो स्पष्ट रूप से भारत द्वारा रियायती रूसी तेल की बड़े पैमाने पर निरंतर खरीद से जुड़ा है। समानांतर रूप से, वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भारत के रूसी–तेल आयात में सार्थक कमी एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक पूर्व शर्त है। नई दिल्ली के लिए, अब गणित बदल गया हैरू ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना सर्वोपरि है, फिर भी उच्च टैरिफ को सहन करने और अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के साथ व्यापार संबंधों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम ने यथास्थिति को तेजी से अस्थिर बना दिया है। अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में अचानक वृद्धि आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय रिफाइनर मिडलैंड डब्ल्यूटीआई और मार्स जैसे अमेरिकी ग्रेड के कच्चे तेल की बुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने हाल के हफ्तों में व्यापक ब्रेंट–डब्ल्यूटीआई प्रसार और कमजोर चीनी मांग के कारण एक व्यवहार्य आर्बिट्रेज की पेशकश की है। हालांकि, विश्लेषक आगाह करते हैं कि यह संरचनात्मक पुनर्संरेखण के बजाय एक अस्थायी उपाय हैरू लंबी समुद्री यात्रा, अमेरिकी ग्रेड से कम उत्पादन और अधिक माल ढुलाई अभी भी इस बदलाव को निकट भविष्य में सीमित कर सकती है। फिर भी, यह तेजी एक मजबूत संदेश देती हैरू नई दिल्ली अपने सोर्सिंग निर्णयों को भू–राजनीतिक रूप से अधिक लचीला बनाने की क्षमता प्रदर्शित कर रही है। तेल बाजार की प्रतिक्रियाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि व्यापारी पहले से ही भारत द्वारा बड़े पैमाने पर रूसी तेल खरीद के अंत की आशंका जता रहे हैं। हाल के वर्षों में वैश्विक मूल्य गतिशीलता में एक प्रमुख कारक, यूराल क्रूड द्वारा प्राप्त छूट कम हो गई है, जबकि भारत में व्यापार करने वाले कार्गो बाजारों में जोखिम प्रीमियम बढ़ गया है। वास्तव में, रूस द्वारा छूट वाले बैरल को स्थिर करने वाले के रूप में भारत की पूर्व भूमिका उलट गई है, जिससे वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों के बीच पुनर्संतुलन को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर, भारी छूट वाले रूसी बैरल को छोडने से रिफाइनरियों का लागत आधार बढ़ जाएगा, जिससे संभावित रूप से डाउनस्ट्रीम ईंधन और पेट्रोकेमिकल मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ती अस्पष्टता के बीच रिफाइनरों को अनुबंधा–रोलओवर के फैसलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कुछ ने प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़ी बुकिंग पहले ही रद्द कर दी हैं, वहीं अन्य बैंकों और बीमा कंपनियों से इस बारे में स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं कि क्या प्रतिबंधित उत्पादक आपूर्ति श्रृंखला को द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम को बढ़ाए बिना सेवा प्रदान की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि भले ही भारत के सार्वजनिक बयान अस्पष्ट हैं, और सरकार औपचारिक रूप से किसी भी निर्देश जारी होने से इनकार कर रही है, व्यवहार में उद्योग जगत के खिलाड़ी अपने व्यवहार को अपेक्षित नीतिगत परिणामों के अनुरूप बना रहे हैं। राजनीतिक गणना स्पष्ट हैरू अमेरिकी मांगों को मानना महंगा है, फिर भी अनुपालन न करने से भारत के विकास मॉडल के लिए बड़े जोखिम हैं, जहां ऊर्जा लागत, व्यापार पहुंच और कूटनीतिक लचीलापन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। रूस के लिए यह घटनाक्रम एक रणनीतिक झटका है, हालांकि घातक नहीं। मास्को अपने रियायती कच्चे तेल के लिए एक प्रमुख स्रोत खो देगा, जिससे उसे या तो चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी या कहीं और ज्यादा छूट देनी पड़ेगी। हालांकि, चीन की अतिरिक्त बड़ी मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता उसकी अपनी आयात सीमा और वैश्विक व्यापार परिदृश्यों से सीमित हैरू इसका मतलब है कि आगे चलकर मास्को को आपूर्ति–श्रृंखला पर और अधिक दबाव और मार्जिन पर अतिरिक्त दबाव का

सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के नजरिए से, ऊर्जा व्यापार का लीवर कारगर रहा है। भारत को मजबूर कर उसके अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में वृद्धि और रूसी बैरल पर अपनी निर्भरता कम करके, वाशिंगटन उस क्षेत्र में अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है जिसे वह बीजिंग के साथ अपनी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही, अमेरिकी उत्पादकों को एक नया बाजार मिलता है, जो श्अमेरिका फर्स्टश ऊर्जा–निर्यात एजेंडे के साथ मेल खाता है। नई दिल्ली के लिए, यह बदलाव कठिन और जटिल हैरू सरकार को सस्ती ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखनी होगी, रिफाइनिंग मार्जिन की व्यवहार्यता बनाए रखनी होगी, और अपनी बहुध्रुवीय कूटनीति की रक्षा करनी होगी – और साथ ही वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह में बदलती शक्ति–खेल के अनुकूल ढलना होगा। इस बदलाव के लिए भारत की लाभ संरचना तात्कालिक नहीं है। हालांकि रूसी कच्चे तेल से दूर जाने से भू–राजनीतिक जोखिम कम होता है, लेकिन इससे मास्को द्वारा दी जाने वाली भारी छूट तक पहुंच भी कम हो जाती है– एक ऐसी छूट जिसने भारत को अपने आयात बिल को कम करने और घरेलू उद्योग के मार्जिन को सहारा देने में मदद की थी। अमेरिकी ग्रेड की डिलीवरी लागत अधिक होने और मध्य–पूर्वी विकल्पों के भारत की भारी–रूपांतरण रिफाइनरियों के लिए कम अनुकूल उत्पाद प्रोफाइल होने के कारण, मार्जिन में कमी वास्तविक है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन के लिए पाइपलाइन, माल ढुलाई और संविदात्मक अनुकूलन की आवश्यकता होगी– इनमें से कोई भी संक्रमणकालीन व्यवधानों के बिना रातोंरात नहीं हो सकता।

एसआईआर शुरू करने में राजनीतिक बाधा

अजीत द्विवेदी

चुनाव आयोग मतदाता सूची की सफाई के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू कर चुका है। अगले साल चुनाव वाले चार राज्यों के साथ साथ 12 राज्यों में यह प्रक्रिया चलेगी। इन 12 राज्यों में मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है और चार नवंबर से पहले चरण यानी मतगणना प्रपत्र भरे जाने की शुरुआत होगी। नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी और एक महीने तक आपत्ति, दावे लिए जाएंगे। सात जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इन 12 राज्यों से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का बिहार में परीक्षण किया था, जो सफल रहा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने इस कामयाबी का जिक्र भी किया। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि बिहार में उसके काम में कितनी बाधाएं आईं और राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों को कैसी लड़ाई लडनी पड़ी। बिहार में एसआईआर को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उसकी सुनवाई अभी चल ही रही है। इसी आधार पर कई पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारधीन है और अंतिम फैसला नहीं आया है तो चुनाव आयोग को दूसरे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं शुरू करनी चाहिए थी। हालांकि उसमें आयोग यह तर्क दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में भी एसआईआर पर रोक नहीं लगाई थी इसलिए दूसरे राज्य में इसे शुरू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। ठीक बात है कि दूसरे राज्य में इसे शुरू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है लेकिन राजनीतिक बाधा है और कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं। जैसे बिहार में 10 हजार ऐसे लोगों के नाम कटे हैं, जिनको नाम काटने वाली किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसी तरह स्थायी रूप से शिफ्ट हो जाने की जो श्रेणी है उसे लेकर भी आपत्ति है क्योंकि स्थायी रूप से बहुत कम लोग शिफ्ट होते हैं। ज्यादातर लोग अंततरू वापस लौटते हैं और अपने स्थायी पते के ही वासी होते हैं। कोरोना के समय या दूसरे आर्थिक संकट के समय यह देखने को मिला है कि लोग अपने घरों को लौटे हैं। स्थायी रूप से शिफ्ट हो जाने वाली श्रेणी में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। तभी चुनाव आयोग को बहुत सावधानी बरतने की जरुरत होगी ताकि ऐसे लोगों के नाम नहीं कटें, जो अपने स्थायी पते पर नहीं रहते हैं लेकिन दूसरी जगह के मतदाता नहीं हैं और स्थायी पते पर ही मतदाता बने रहना चाहते हैं। ऐसे प्रवासियों के लिए बूथ लेवल अधिकारी के तीन बार उसके पते पर जाने का नियम पर्याप्त नहीं है। बिहार में ऐसा देखने को मिला कि बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ तीन बार तो छोडिघ्ए एक बार भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा। कई जगह सफाईकर्मी या दूसरे कर्मचारियों के हाथों मतगणना प्रपत्र भेजे गए। खाली घरों के आसपास ज्यादा से ज्यादा एक बार पूछताछ हुई और नाम काट दिया गया। अस्थायी रूप से कहीं गए लोगों के भी नाम कटे। चुनाव आयोग को यह ध्यान रखना होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया उसने मतदाता सूची की सफाई के लिए चलाई है, लोगों के मताधिकार छीनने के लिए नहीं। उसकी कोशिश यह होनी चाहिए कि मृत मतदाताओं या एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज नाम वाले मतदाताओं के नाम काटे लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। बिहार के अनुभव के आधार पर उसे इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए सहज और सरल बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। जिस तरह की खबरें और तस्वीरें बिहार से एसआईआर की आईं वैसी दूसरे राज्यों से नहीं आनी चाहिए। आयोग को भी पता है कि कैसे बूथ लेवल अधिकारियों ने अपने घरों में बैठ कर मतगणना प्रपत्र भरे और उन्हें जमा कर दिया। कैसे पहले से भरे हुए दो मतगणना प्रपत्र की जगह मतदाताओं को एक प्रपत्र दिया गया। मतदाताओं पर छोड़ दिया गया कि वे इसकी फोटोकॉपी कराएं। मतदाताओं की तस्वीरों के मामले में भी कई तरह की गड़बडियां हुईं। नाम, पता, लिंग आदि की विसंगतियां तो अब भी बड़ी संख्या में मतदाता सूची में हैं।

एनडीए के घोषणापत्र में ज्यादा दम है महागठबंधन के वादों की बारिश के बीच मतदाता को क्या भायेगा?

नीरज

बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन दोनों ने अपने–अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों जीतन राम मांझी, चिराग पासवान तथा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में एनडीए ने अपना विस्तृत घोषणापत्र प्रस्तुत किया। एनडीए के घोषणापत्र में एक करोड़ रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर दिया गया है। घोषणापत्र में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, औद्योगिक पार्क, महिला उद्यमिता मिशन, खेती के लिए एमएसपी की गारंटी, और सात नए एक्सप्रेसवे जैसी योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके साथ ही गरीबों के लिए 50 लाख नए घर, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और बेहतर शिक्षा–स्वास्थ्य ढांचा का वादा किया गया है। राजग के घोषणा पत्र के प्रमुख प्रावधानों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आर्थिक सहायता का भी उल्लेख है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) को सरकार 10 लाख रुपये की सहायता देगी और उनके हितों के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित किया जाएगा। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के लिए राजग ने 'कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' शुरू करने की घोषणा की है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से लागू किया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी और कृषि अवसंरचना में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। घोषणापत्र में कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार को अगले पांच वर्षों में पूरी तरह इस समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी विकास के तहत चार और शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की घोषणा भी की गई है। राजधानी क्षेत्र में "न्यू पटना" नामक एक हरित (ग्रीनफील्ड) परियोजना विकसित की जाएगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जानकी मंदिर को "सीतापुरम" के रूप में विकसित किया जाएगा। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि बिहार से विदेशी उड़ानें शुरू की जाएंगी और कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। साथ ही, राज्य में 10 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक जिले में फैक्टरी एवं विनिर्माण इकाइयां शुरू की जाएंगी। राजग ने वादा किया है कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे "औद्योगिक क्रांति" की गारंटी सुनिश्चित होगी। शिक्षा के क्षेत्र में राजग ने "केजी से पीजी तक निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" का वादा किया है। अनुसूचित जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजग ने गरीब और वंचित वर्गों के लिए 'पंचामृत गारंटी' की घोषणा की है, जिसके तहत मुफ्त राशन, पांच लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, 50 लाख पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित की जाएगी राजग ने घोषणापत्र में कहा कि खेल के क्षेत्र में राज्य में 'बिहार स्पोर्ट्स सिटी' का निर्माण किया जाएगा ताकि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिल सकें। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। घोषणा पत्र के अनुसार, गिग वर्कर्स और ऑटो चालकों को वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भाजपा ने कहा, "यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार के भरोसे का प्रतीक है।" दूसरी ओर, महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र जिसे 'तेजस्वी प्रणश नाम दिया गया है, में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि "हम सत्ता में आए तो 20 दिन में हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी।" घोषणापत्र में 'जीविका दीदी' को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने और युवा, किसान व महिला सशक्तिकरण से जुड़ी 25

प्रमुख घोषणाएँ शामिल हैं। देखा जाये तो बिहार की राजनीति में घोषणापत्र अब केवल नीतिगत दस्तावेज नहीं रहे, बल्कि भावनात्मक प्रोपेगेंडा बन चुके हैं। इस बार दोनों खेमों ने वादों की ऐसी बारिश की है कि आम मतदाता के लिए असली और नकली बादल में फर्क करना मुश्किल हो गया है। एनडीए का घोषणापत्र दिखने में व्यावहारिक और संरचनात्मक हैकृ यह विकास, उद्योग और स्थिरता की बात करता है। वहीं महागठबंधन का घोषणापत्र भावनात्मक हैकृ यह नौकरी, वेतन और सरकारी स्थायित्व जैसे सीधे वादे करके युवाओं के दिलों को छूने की कोशिश करता है। एनडीए ने इस बार 'गारंटी' को मुख्य शब्द बनाया है। "मोदी की गारंटी और नीतीश का भरोसा", यह नारा सीधे जनता की याद्दाश्त में बैठाने की रणनीति है। घोषणापत्र का फोकस बुनियादी ढांचे पर है। जैसे– 7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किमी नई रेल लाइनें, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक पार्क का वादा किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में उद्योग लगाने का माहौल तैयार है? बिजली, भूमि, कानून व्यवस्था और मानव संसाधन, ये चारों चुनौतियाँ अभी भी गंभीर हैं। देखा जाये तो एक करोड़ रोजगार का वादा तब तक महज नारा रहेगा जब तक बिहार में पूंजी निवेश आकर्षक नहीं बनता। हालाँकि, एनडीए ने महिलाओं पर केंद्रित योजनाओंकृ "लखपति दीदी मिशन" और "महिला उद्यमिता योजनाश के जरिए ग्रामीण महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का पिछला रिकॉर्ड इस दिशा में अपेक्षाकृत मजबूत रहा है, इसलिए इस वर्ग में एनडीए का वादा विश्वसनीय दिखता है। वहीं तेजस्वी यादव ने घोषणापत्र को पूरी तरह युवाओं के लिए डिजाइन किया है। "20 दिन में नौकरी" जैसा वादा तात्कालिक रूप से आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन वित्तीय दृष्टि से यह असंभव है। बिहार के राजस्व संसाधन सीमित हैंय अगर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, तो यह न केवल आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होगा बल्कि शासन व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। पुरानी पेंशन योजना, ठेका कर्मियों का स्थायीकरण और 'जीविका दीदी' को सरकारी दर्जा देने जैसी घोषणाएँ वित्तीय बोझ को कई गुना बढ़ा सकती हैं। महागठबंधन ने भावनात्मक राजनीति का सहारा लिया है,।

बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेरा, खेत में खड़ी व काटकर सुखाने के लिए रखी धान की फसल खराब

लखनऊ, (संवाददाता)। बृहस्पतिवार सुबह से शाम तक हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं खेत में सुखाने के लिए काट कर रखी गई धान की फसल भीग कर खराब हो गई है तो कहीं खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसल नष्ट हो रही है। धान, सरसों, मटर, आलू जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की महीनों की मेहनत पर बारिश ने पानी फेर दिया है। इससे उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही है। मोहनलालगंज प्रतिनिधि के अनुसार क्षेत्र के सिसेंडी, मऊ, जबरौली, भदेसुवा, गनियार, भौंदरी गांव के किसानों की धान, सरसों, मटर व आलू की फसल चौपट हुई है। गनियार के किसान अजय पाल ने बताया कि खेतों में कटी पड़ी धान की फसल भीगने पर अंकुरित हो सकती है। जो फसल खड़ी है उसे भी नुकसान पहुंचा है। कुछ किसान सरसों, मटर व आलू की बोआई कर चुके हैं। इनकी फसल को भी नुकसान हुआ है। विकासखंड काकोरी के प्रतिनिधि के अनुसार, बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। चौखड़ी खेड़ा गांव निवासी प्रधान गुरु दयाल ने बताया कि खेतों में खड़ी और कटी हुई धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बसंत खेड़ा गांव के बलवीर यादव ने बताया कि आलू की नई बोआई पर असर पड़ा है। दसदोई के अखिलेश उर्फ गब्बर गौतम ने बताया कि गोभी और मटर की फसलें भी बारिश की मार झेल रही हैं। काकोरी के आजाद चौधरी, खानपुर मऊ निवासी वीरेंद्र यादव ने बताया कि बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे सभी फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. एके दुबे ने बताया कि गोसाईंगंज, बीकेटी, मलिहाबाद व काकोरी में किसान धान की अच्छी खेती करते हैं। धान की अधिकतर फसलें कटने के कगार पर हैं, जबकि काफी किसानों के खेतों में खड़ी धान की फसल कट कर सुखाने के लिए रखी है। दोनों ही स्थिति में धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। खड़ी फसल का उत्पादन 20 तो कटी फसल का उत्पादन करीब 30 फीसदी कम हो जाएगा। जिन किसानों ने हाल ही में आलू, चना, मटर और सरसों की अगेती बोआई की है और उसका जमाव अभी ठीक से नहीं हो सका है। ऐसे सभी फसलों के जमाव पर बारिश का प्रभाव पड़ेगा। बीज के भीग कर सड़ने की संभावना अधिक रहेगी। जिन किसानों ने दलहनी, तिलहनी फसलों के साथ गोभी, पालक, धनिया बोने के लिए खेत तैयार किए थे, बारिश के कारण अब उनको खेत सूखने का इंतजार करना होगा। इससे बोआई में देरी होगी। नगराम प्रतिनिधि के अनुसार बचनखेड़ा निवासी किसान रमेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने उनकी सूखने के लिए खेतों में पड़ी धान की फसल बारिश से भीग चुकी है। इससे दाने खराब होने का डर है। सिरौना के भगौती का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सरोजनीनगर क्षेत्र के किसानों की भी यही चिंता है। निगोहां के किसान पुप्पन तिवारी ने बताया कि खेत में लगभग पांच बीघे की फसल कटी पड़ी हैं। आज इनकी पिटाई शुरू होनी थी, लेकिन बारिश ने सब चौपट कर दिया। किसान आनंद मोहन तिवारी ने बताया कि बुधवार शाम को लगभग तीन बीघे तिलहन की बोआई कराई थी,।

आठ लोग अभी भी लापता, तीसरे दिन सर्च अभियान जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। बहराइच के भरथावल नाव हादसे के तीसरे दिन भी लापता आठ लोगों का पता नहीं चल सका है। शुक्रवार सुबह से ही कौड़ियाला नदी में घटनास्थल से लेकर घाघरा बैराज तक लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च अभियान शुरु कर दिया है। नदी में हर 500 मीटर की दूरी पर अलग–अलग सर्च टीमों को तैनात किया गया जो अपने 500 मीटर के दायरे में मोटरबोट से रेस्क्यू

कर रहे हैं। मौके पर डीएम व एसपी सुबह से घाघरा बैराज पर मौजूद हैं जो मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बुधवार की देर शाम बहराइच के ट्रांस गेरुआ क्षेत्र में कौड़ियाला नदी में यात्रियों से भरी एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई। जबकि, 13 लोग तैरकर बाहर निकल आए। मासूम बच्ची कोमल (5) पुत्री पंचम समेत आठ लोग अभी भी लापता हैं। गुरुवार को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और एसएसबी की टीमें इनकी तलाश में जुटी हैं।

संक्षिप्त खबरें

70 निजी अस्पतालों का दोबारा होगा निरीक्षण

लखनऊ, (संवाददाता)। दमकल विभाग शहर के उन 70 निजी अस्पतालों का दोबारा निरीक्षण करेगा, जिन्हें लोकबंधु अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद पूर्व सीएफओ ने लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया था। इन अस्पतालों ने अब भी आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम नहीं मिले तो इनका लाइसेंस निरस्त करने के साथ बिजली कनेक्शन भी काटा जाएगा। सीएफओ अंकुश मित्तल ने बताया कि पूर्व सीएफओ ने जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किया था, उनका किसी कारणवश लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ था। ऐसे 70 अस्पतालों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। इनके साथ ही पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, केजीएमयू, झलकारी बाई व शहर के अन्य 64 अस्पतालों (जिनके पास फायर एनओसी नहीं थी) का भी निरीक्षण होगा। इन्होंने अब तक एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया होगा तो विभाग कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। फिर भी न सुधरने पर विभाग बड़ी कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि सोमवार सुबह आलमबाग स्थित उत्तर रेलवे मंडल चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इससे भर्ती 22 मरीजों की जान सांसत में आ गई थी। 250 बेड के अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के नाम पर सिर्फ फायर एस्टिंगुशर लगे थे। दमकल विभाग ने अस्पताल को नोटिस जारी किया है।

इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला को इसरो के आउटरीच नोडल नेटवर्क संस्थान के रूप में मान्यता

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), देहरादून के आउटरीच नोडल नेटवर्क संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इस मान्यता के साथ नक्षत्रशाला अब इसरो के राष्ट्रीय आउटरीच प्रोग्राम नेटवर्क से औपचारिक रूप से जुड़ गया है। यह उपलब्धि प्रदेश में विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।इसरो नेटवर्क से जुड़ने के बाद अब इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में एस्ट्रोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस (ळमवहतंचीपब प्दवितउंजपवद ैलेजमउ), ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, फोटोमेट्री सहित अंतरिक्ष से संबंधित अन्य अनुप्रयोगों पर आधारित विविध प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव एवं उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक पंधारी यादव ने कहा कि "इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला को यह मान्यता मिलना राज्य के बढ़ते वैज्ञानिक वातावरण और योगी सरकार की विज्ञान–प्रेरित नीतियों की बड़ी उपलब्धि है। इससे विद्यार्थियों में अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रदेश में वैज्ञानिक नवाचार को नई दिशा मिलेगी।" विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव शीलधर सिंह यादव ने कहा कि "इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का इसरोदृआईआईआरएस आउटरीच नेटवर्क में शामिल होना परिषद के उस उद्देश्य के अनुरूप है, जिसके तहत राज्यभर में विज्ञान, नवाचार और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार का कार्य किया जा रहा है।

महापौर–नगर आयुक्त में विवाद लगा सकता है विकास में अड़ंगा

लखनऊ, (संवाददाता)। महापौर सुषमा खर्कवाल व नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच तनातनी का शहर के विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। पिछले 25 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जब नगर निगम के दो मुखिया इस तरह से आमने– सामने हैं। विवाद बढ़ा तो अगले महीने आने वाला नगर निगम का पुनरीक्षित बजट भी अटक जाएगा। इसका असर शहर में सफाई, सड़कों की मरम्मत, मार्ग प्रकाश सहित अन्य कार्यों पर पड़ेगा। नगर निगम का मूल बजट 31 मार्च से पहले पास किया जाता है, जो एक अप्रैल से लागू होता है। मंजूर किए बजट से अधिक नया पास होने से पहले खर्च हो जाए या ऐसा होने का अनुमान होता है तो अक्तूबर में पुनरीक्षित बजट लाया जाता है। नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के तहत पुनरीक्षित बजट अक्तूबर के पहले सप्ताह में पास हो जाना चाहिए, पर अब तक ऐसा नहीं हो सका। इसके लिए कार्यकारिणी बैठक बुलाई जाती है। इसमें बजट मंजूर होने के बाद उसे सदन में पास किया जाता है। अब विवाद से लग रहा है कि बजट दिसंबर तक पास नहीं हो पाएगा। इससे नगर निगम के कामकाज व विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। तैयार किए जा रहे पुनरीक्षित बजट के हिसाब से 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट नगर निगम को सफाई, मार्ग प्रकाश और सड़क निर्माण आदि के लिए बढ़ाना पड़ेगा। नई सड़क बनाने के लिए दो करोड़, पार्कों के रखरखाव के लिए 23 करोड़, सड़कों की मरम्मत के लिए करीब 45 करोड़, नाले बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट बढ़ाने की जरूरत है। कई और मदों में बजट बढ़ाने की जरूरत है। महापौर सुषमा खर्कवाल का कहना है कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए डेढ़ वर्ष पहले मशीन खरीदी गई थी। उससे भरे गड्ढे ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। उनका यह भी कहना है कि शहर के विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। अफसर मनमानी करेंगे तो कार्यकारिणी बैठक में बजट को पास किया जाएगा। पैचवर्क के लिए एक सप्ताह में 15 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया जाएगा। कार्यकारिणी और सदन पास करता है बजटरू नगर आयुक्त नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि बजट नगर निगम कार्यकारिणी व सदन पास करता है। फिर प्रशासन इसे लागू करता है। कई कार्यों में दिक्कत इसलिए आ रही है, क्योंकि पिछली नगर निगम सदन की कार्यवाही को अभी तक अनुमोदित कर जारी नहीं किया गया है। इससे सदन में पास हुए प्रस्तावों पर अमल नहीं हो पा रहा है।

निजी हाथ में होगी गोमतीनगर स्टेशन की कमान

लखनऊ, (संवाददाता)। अमौसी एयरपोर्ट की तर्ज पर गोमतीनगर स्टेशन की कमान भी निजी हाथों में सौंपी जाएगी। यहां से ट्रेनों का संचालन, सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की होगी। टिकटिंग, सफाई, फूड प्लाजा, पार्किंग, मेंटेनेंस का काम प्राइवेट एजेंसी संभालेगी। इसके लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) टेंडर कर प्राइवेट एजेंसी चुनेगा। यह यूपी का पहला स्टेशन होगा जिसकी कमान निजी हाथों में होगी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोमतीनगर स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का काम जल्द पूरा होगा। इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।

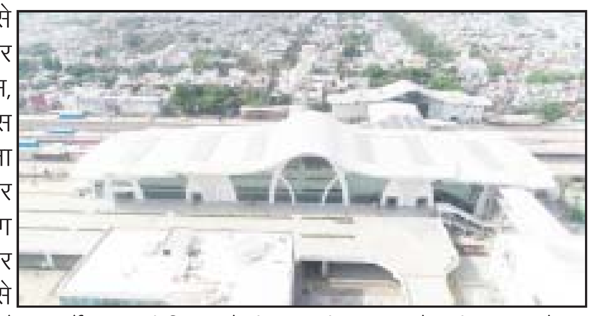

प्रीमियम ट्रेनें की जाएंगी शिफ्टरू जंक्शन से चलने वाली प्रीमियम ट्रेनों को गोमतीनगर स्टेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। पुष्पक एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी, डबलडेकर एक्सप्रेस आदि को गोमतीनगर शिफ्ट करने की योजना है। स्टेशन पर मॉल, एसी लाउंज से लेकर फूड प्लाजा भी रहेगा। 775 वाहनों की पार्किंग होगी तथा आवाजाही एयरपोर्ट की तर्ज पर रहेगी। स्टेशन पर आगमन फर्स्ट फ्लोर से होगा तथा निकासी ग्राउंड फ्लोर से रहेगी। प्लेटफॉर्मों तक सीमित रहेगी आरपीएफरू गोमतीनगर स्टेशन पर सुरक्षा निजी हाथों में रहेगी। आगमन व प्रस्थान से लेकर सरकुलेटिंग एरिया तक में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। आरपीएफ ट्रेनों में जांच करेगी तथा प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा संभालेगी। आरएलडीए निभाएगा अहम भूमिकाः गोमतीनगर रेलवे स्टेशन को विकसित करने में ही आरएलडीए की भूमिका नहीं रहेगी। यह प्राइवेट एजेंसी के चयन से लेकर उसकी निगरानी तक में अहम भूमिका अदा करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ट्रेनों का संचालन, कंट्रोल रूम, सेफ्टी वगैरह करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल का कहना है कि गोमतीनगर स्टेशन पर टिकटिंग, कॉमर्शियल, पार्किंग, खानपान, सिक्योरिटी आदि के काम निजी एजेंसी करेगी। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ तैनात रहेगी। ट्रेनों का संचालन रेलवे के हाथ में होगा। आरएलडीए निजी एजेंसी के चयन के लिए टेंडर करेगा।

संक्षिप्त खबरें

प्रदेशभर में भव्यता से मनाया जाएगा सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती का राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शासन ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती, 31 अक्टूबर 2025, को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में अत्यंत भव्यता और सम्मानपूर्वक मनाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि सरदार पटेल की जयंती पूरे देश में हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह दिन स्वतंत्र भारत के एकीकरण में उनके अद्वितीय योगदान को स्मरण करने और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का प्रतीक है।राज्य सरकार ने सभी विभागों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस को गरिमापूर्वक और संगठित रूप में मनाया जाए। इस अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विभागीय परिसरों में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।"मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस अवसर पर राज्यभर में विभिन्न सांस्कृतिक और जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इन कार्यक्रमों में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों के विद्यार्थी, अधिकारी एवं नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

मानवता और सेवा का संदेशरू प्रदेशभर में पुलिस के सहयोग से आयोजित होंगे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर

लखनऊ, (संवाददाता)। रूमानवता और सेवा की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य रक्त संचरण परिषद एवं पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आगामी नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पूरे प्रदेश में एक साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का लक्ष्य न केवल रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, बल्कि समाज में परोपकार और जनसेवा की भावना को भी सशक्त बनाना है।राज्य रक्त संचरण परिषद के निदेशक ने अपने विशेष संदेश में कहा कि "रक्तदान सबसे बड़ा दान है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नई जिंदगी दे सकता है।" उन्होंने समाज के सभी स्वस्थ नागरिकों से इस महायज्ञ में भाग लेने की अपील की, ताकि किसी भी मरीज को रक्त की कमी के कारण अपना जीवन न गंवाना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस मुख्यालय का इस अभियान में सहयोग सराहनीय है, जिससे पूरे प्रदेश में पुलिस बल की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रक्तदान करेंगे। रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र और धन्यवाद पत्र प्रदान कर उन्हें इस मानवसेवा के कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा।राज्य रक्त संचरण परिषद ने जनसामान्य से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की है। परिषद के निदेशक ने कहा "आइए, जीवन बचाने के इस अभियान में पुलिस बल के साथ कदम से कदम मिलाएँ ।

लखनऊ में खुलेगा उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय, शासनादेश जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय भी लखनऊ में खोला जाएगा। शासन की ओर से आदेश जारी कर उच्च शिक्षा निदेशक से इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। फिलहाल कैंप कार्यालय सरोजनी नगर के लतीफ नगर में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय परिसर में खोला जाएगा। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में है। अब उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय भी लखनऊ में खोला जाएगा। पूर्व में भी इस बाबत आदेश जारी किया गया था लेकिन कर्मचारियों के तीव्र विरोध के बाद इस फैसले को स्थगित कर दिया गया था। शासन की ओर से अब एक बार फिर लखनऊ में कैंप कार्यालय खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसे लेकर विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से उच्च निदेशक को पत्र लिखा गया है। पत्र के अनुसार पिछले दिनों समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया ताकि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ शासकीय कार्यों को त्वरित और प्रभावी तरीके से निस्तारित किया जा सके। नया भवन मिलने तक कैंप कार्यालय लखनऊ में सरोजनी नगर स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा गया है। शासन से आदेश आने के बाद कैंप कार्यालय के स्वरूप, इसमें किन–किन अफसरों और कर्मचारियों की तैनाती होगी, जरूरी कागजातों की शिफ्टिंग आदि बिंदुओं पर मंथन शुरू हो गया है। इसके लिए शासन से गाइडलाइन भी मांगी गई है। अफसरों का कहना है कि जरूरी कार्रवाई कर जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर कैंप कार्यालय के संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लखनऊ में कैंप कार्यालय खोले जाने के आदेश से निदेशालय में हलचल तेज होने के साथ कर्मचारियों के विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय लखनऊ में खोले जाने का तीव्र विरोध किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा का भी कैंप कार्यालय लखनऊ में है लेकिन धीरे–धीरे निदेशालय के ज्यादातर काम वहीं चले गए। यहां महज औपचारिकता भर रह गई है। आशंका है कि लखनऊ में कैंप कार्यालय खुलने से उच्च शिक्षा निदेशालय का भी यही अंजाम होगा। धीरे–धीरे सभी काम वहीं चले जाएंगे। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि शासन की मंशा है कि सभी विभागों के मुख्यालय लखनऊ में शिफ्ट कर दिए जाएं। पुलिस मुख्यालय, निबंधान कार्यालय, राजस्व परिषद समेत कई विभागों के ज्यादातर काम लखनऊ शिफ्ट हो चुके हैं। कर्मचारियों को आशंका है कि उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय खोला जाना भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय का लखनऊ में कैंप कार्यालय खोले जाने का विरोध किया गया। संघ की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर यह आदेश निरस्त करने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री प्रयागराज के गौरव के लिए लगातार प्रयासरत हैं लेकिन यह आदेश शिक्षा नगरी की गरिमा के साथ अन्याय है। उनका कहना था कि निदेशालय में एक करोड़ रुपये की लागत से ई–कंटेंट स्टूडियो स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से निदेशालय के अधिकारी और शासन के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे जुड़कर कार्यों को निस्तारित कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष घनश्याम यादव और मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से लखनऊ में निदेशालय का कैंप कार्यालय खोले जाने का आदेश निरस्त करने की मांग की।

विकसित उत्तर प्रदेश 2047 महाभियान में अब तक 66.85 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त, जनभागीदारी बनी विकास की आधारशिला

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान 'समर्थ उत्तर प्रदेशदृ विकसित उत्तर प्रदेश2047दृसमृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान' के अंतर्गत प्रदेशभर में चल रही जनसंवाद एवं सहभागिता की प्रक्रिया ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 30 अक्टूबर, 2025 तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों तथा प्रबुद्ध जनों ने व्यापक भ्रमण कर विभिन्न लक्षित समूहोंकृछात्रों, शिक्षकों, व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषकों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संघों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम नागरिकोंकृ के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान बीते आठ वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा के बारे में जानकारी साझा की गई और आगामी विकास रोडमैप पर विचार–विमर्श करते हुए जनता से मूल्यवान सुझाव प्राप्त किए गए।प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस की राय प्राप्त करने के लिए विकसित पोर्टल upviksit2047-in पर अब तक कुल 66,85,696 फीडबैक दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 52,98,579 सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 13,87,121 सुझाव नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 32,84,658 सुझाव 31 वर्ष से कम आयु वर्ग, 30,87,199 सुझाव 31 से 60 वर्ष आयु वर्ग, और 3,13,844 सुझाव 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा दिए गए हैं। यह आँकड़ा प्रदेश के युवाओं और ग्रामीण नागरिकों की गहरी भागीदारी को दर्शाता है।प्राप्त फीडबैक में कृषि, पशुधन, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा, समाज कल्याण, नगरीय विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे तमाम क्षेत्रों से जुड़ी राय सम्मिलित हैं। इनमें कृषि क्षेत्र से सर्वाधिक 17,39,040 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जबकि शिक्षा क्षेत्र से 15,38,196, ग्रामीण विकास से 13,04,579, समाज कल्याण से 5,15,307, नगरीय और स्वास्थ्य क्षेत्र से 4,54,148 तथा सुरक्षा से 1,26,289 सुझाव दर्ज किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र से 2,42,635, आईटी एवं टेक से 1,87,029, पर्यटन से 1,57,866, पशुधन एवं डेयरी से 2,66,286, संतुलित विकास से 94,322 तथा इंफ्रास्ट्रक्चर से 60,005 सुझाव प्राप्त हुए हैं।जनपदवार स्थिति पर नजर डालें तो जौनपुर 6,53,257 सुझावों के साथ शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद संभल 5,94,577, गाजीपुर 2,60,974, हरदोई 2,07,741 और प्रतापगढ़ 1,80,911 सुझावों के साथ अग्रणी रहे हैं। वहीं इटावा, ललितपुर, बलिया, गौतमबुद्ध नगर और महोबा से सबसे कम फीडबैक प्राप्त हुए हैं। जनसामान्य द्वारा दिए गए सुझावों में प्रदेश के विकास की स्पष्ट दिशा दिखाई देती है। बरेली के योगेश बाबू ने औद्योगिक विकास को आर्थिक प्रगति की रीढ़ बताते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सस्ती ऋण सुविधा, तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग ग्रामीण आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं, जिन्हें आधुनिक मार्केटिंग और ई–कॉमर्स से सशक्त किया जा सकता है। अमरोहा के विभोर जिंदल ने 'स्वच्छता ही सेवा' जैसे अभियानों को जनभागीदारी से जोड़ने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ मिशन तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई को और प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। वहीं हापुर के शिवा ने पशुधन विकास पर बल देते हुए कहा कि पशु स्वास्थ्य, आहार, स्वच्छ पशुशाला, गुणवत्ता नियंत्रण और ऑनलाइन विपणन जैसे उपायों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।महाभियान के अंतर्गत जनसंपर्क और जागरूकता गतिविधियाँ भी बड़े पैमाने पर आयोजित की जा रही हैं। नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर बैठकों एवं गोष्ठियों के माध्यम से नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के बीच संवाद को मजबूत किया गया है। अब तक 215 नगर पालिकाओं में बैठकें, 228 में सम्मेलन, 18 नगर निगमों में बैठकें एवं सम्मेलन, 64 जिला पंचायतों में सम्मेलन, 61 में बैठकें, 557 नगर पंचायतों में बैठकें, 578 नगर पंचायतों में सम्मेलन, 780 क्षेत्र पंचायतों में सम्मेलन, 783 में बैठकें और 51,012 ग्राम पंचायतों में बैठकों का सफल आयोजन किया जा चुका है।इन आयोजनों ने जनता और शासन के बीच जुड़ाव को नई दिशा दी है।

फल–सब्जियां तो खूब आईं, कम पहुंचे खरीदार

लखनऊ, (संवाददाता)। बृहस्पतिवार सुबह से शाम तक हुई रिमझिम बारिश ने राजधानी की सब्जी और फल मंडियों की रौनक फीकी कर दी। सीतापुर रोड स्थित नवीन मंडी में ट्रकों और पिकअप से माल तो भरपूर पहुंचा, लेकिन खरीदारों की कमी ने कारोबारियों और किसानों के चेहरों की चमक उतार दी। आढ़ती सलीम पपीते से भरे ट्रक को तिरपाल से ढककर फुटकर व्यापारियों को बेचते नजर आए। बोले– बाहर से जो भी माल एक–दो दिन पहले चला था वह मंडी तक आ गया, लेकिन बारिश में खरीदार कम मिले। पिकअप में भरे कच्चे केले को रमेश बारिश से बचाने के लिए तिरपाल ढकते नजर आए। बोले– केले भीग गए तो खरीदार अच्छा दाम नहीं देंगे। परवल लौकी लेकर मंडी पहुंचे सिधौली के किसान राजेश शुक्ला और धनिया, लौकी, बींस लेकर मंडी पहुंचे मिश्रिख के तेजपाल ने बताया कि वे रात ही पहुंच मंडी गए थे। बारिश के कारण आसपास के फुटकर व्यापारी कम पहुंचे। मजबूरी में सभी सब्जियां दो से चार रुपये कम दर पर बेचनी पड़ीं। जो माल बच गया उसे आढ़त पर ही रखना पड़ा। बारिश के कारण मंडी समिति में करीब 30 फीसदी दुकानदार कम आए। ऐसे में किसानों और माल लेकर पहुंचे व्यापारियों को शिमला मिर्च, धनिया, आलू, प्याज और टमाटर सभी थोड़े कम दाम पर बेचने पड़े। इसके बाद भी कई किसानों का माल बच गया। सेब कश्मीर से, किन्नू पंजाब से, अमरूद व केला लोकल आ रहा है। सभी प्रचुर मात्रा में मंडी में हैं। बारिश के कारण बृहस्पतिवार को कम व्यापारी खरीदारी के लिए पहुंचे। इस कारण 50 से 100 रुपये प्रति पेटी कम पर माल बेचना पड़ा। बिक्री अन्य दिनों की तुलना में करीब 60 फीसदी तक घट गई। आवक पर बारिश का असर नहीं पड़ा है, लेकिन बिक्री में जरूर कमी आई है।

सामूहिक विवाह जैसी पहल समाज में समानता और सहयोग की भावना को मजबूत करती है : शिव प्रताप शुक्ल (राज्यपाल)

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जनपद के बदलापुर में आयोजित भव्य बदलापुर महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को सामूहिक विवाह समारोह के साथ हुआ। सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज परिसर में सजे रंगीन पंडालों में 685 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसी पहल समाज में समानता और सहयोग की भावना को मजबूत करती है। यह आयोजन जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सुखी, समृद्ध एवं आदर्श पारिवारिक जीवन की शुभकामनाएँ दीं।

दिवसीय बदलापुर महोत्सव में यूपी के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण पहुंचे तथा यहां आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई जा रही शादी में जोड़ो को आशीर्वाद दिया।

उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा बदलापुर महोत्सव की शुरुआत आज से हुआ है जिसका एक प्रमुख आकर्षण मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह है,आज इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी का आगमन हुआ। जाति, धर्म और क्या क्षेत्र सभी लोग इसमे प्रतिभाग कर रहे है,सही मायने में सबका साथ सबका विकास का दृश्य आज बदलापुर में दिख रहा है।यह बदलाव का भी संकेतक है,जिस तेजी के साथ आर्थिक विकास पूरे भारत मे हो रहा है,उसी तेजी के साथ विषमताओं को भी हम दूर कर रहे हैं।किसी प्रकार की कोई भेदभाव नही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि हर गरीब परिवार की बेटी का विवाह गरिमा के साथ हो। इस प्रकार के आयोजन सामाजिक सरोकारों को नई दिशा देते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे व सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा दिये बयान कि सरदार पटेल ने भाजपा की पैतृक पार्टी आरएसएस पर बैन लगाया था,आज भी इसकी जरूरत है,इस पर असीम अरुण ने कहा कि सरदार पटेल जी की 150 वी जयंती हम सब ने मनाई, उन्होंने जो योगदान दिया उन सबको हमने याद किया,उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया,जो अखंडता में विश्वास रखते थे।देश को जोड़ने का उन्होंने काम किया।आज समाजवादी पार्टी केवल तोड़ने वाला काम किया है ।

भगवान की भक्ति जरूरी – आचार्य बालकृष्ण महाराज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। खेतासराय क्षेत्र के अतरहीं गांव में श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह का हवन पूजन और भंडारे के पश्चात शुक्रवार की देर शाम समापन हो गया। इस दौरान कथावाचक आचार्य बालकृष्ण महाराज प्रयागराज ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हमको मनुष्य का जीवन मिला है और श्रीमद्भागवत जी की कथा श्रवण मात्र से ही इस जीवन का उद्धार हो जाता है। हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो भगवान की भक्ति छोड़कर बाकी सारे काम करता है, लेकिन जब अंत समय आता है तब वह भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि जब से हम सोचने, समझने लायक हो, तब से ही हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। माता–पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को भगवान की भक्ति से जोड़ें ताकि उसका बचपन से ही भगवान में जुड़ाव हो सके। मुख्य यजमान छबिनाथ तिवारी, उनके पुत्र सूरज तिवारी और पुत्रवधू स्नेहा तिवारी ने पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लिया। हवन पूजन के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आशीष मिश्रा, विवेक मिश्रा, रविकांत मिश्रा, मनीष तिवारी, अवनीश, वीरेंद्र, नीरज तिवारी कार्तिक, आकाश, आदर्श, अभिषेक, सर्वज्ञ समेत कई लोग मौजूद रहे। आयोजक सूरज तिवारी ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

रामनगरी के हर चौराहे व मार्गो पर जाम लगने से शहरवासी रहते है घंटो परेशान

अयोध्या। राम भरोसे शहर की यातायात व्यवस्था चल रही है।शहर का कोई ऐसा ही चौराहा या फिर मार्ग शायद ही बचा हो जहां पर आपको जाम ना मिले।और यह जाम केवल कुछ मिनट तक ही नहीं बल्कि कई घंटों तक आप इस जाम में फंसे रहेंगे यहां तक की इधर से गुजरने वाले खासकर एंबुलेंस के माध्यम से मरीज छात्रों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है।इस संबंध में जब यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका यही रटा रटाया उत्तर रहता है कि जाम की कोई समस्या शहर मे नहीं है।कोतवाली नगर क्षेत्र के कसाबबाडा, रिकाबगंज, जिला महिला चिकित्सालय, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, देवकाली बाईपास, नाका बाईपास, रायबरेली बाईपास मार्ग, चौक, फतेहगंज, रिकाबगंज, नियांवा,गुदरी बाजार सहित कई ऐसे प्रमुख चौराहे व मार्ग हैं जहां पर जाम लगना आम बात है।और यह जाम सुबह देर शाम तक बनी रहती है।जिसके चलते स्कूली बच्चे, मरीज, बाहर से आने वाले श्रद्धालु व अन्य राहगीर, दो पहिया व चार पहिया वाहन चालक इस जाम मे घंटो फंसे रहते है। परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी ध्यान नहीं दे रहे है।देखा जाये तो इन चौराहों पर आपको एकाद यातायात के सिपाही मिलेंगे। आधा चौराहा आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ना तो यातायात सिपाही तैनात मिलेंगे और ना ही यातायात ट्रैफिक लाइट से भीड़ को कंट्रोल करते हुए मिलेगी।इस संबंध में जब यातायात को सुरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया की विभाग में यातायात पुलिस कर्मी पर्याप्त संख्या में है लेकिन प्रमुख चौराहों पर यातायात का नियंत्रण ट्रैफिक लाइट द्वारा होता है।

"एस.के.डी. परिवार की प्रेरणा : श्री एस.के.डी. सिंह सर को 81वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।"

सिटी रिपोर्टर प्रत्यूष पाण्डेय

लखनऊ। एस.के.डी. परिवार ने अपने आदरणीय संस्थापक एवं चेयरमैन श्री एस. के. डी. सिंह सर का 81वां जन्मदिन अपार श्रद्धा, प्रेम और उल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजन समारोह से हुआ, जिसके पश्चात विद्यार्थियों व शिक्षकों ने चेयरमैन सर का स्वागत किया और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। विद्यालय का वातावरण प्रेम, आदर और प्रेरणा से भर गया। निदेशक श्री मनीष सिंह ने अपने संदेश में कहा कृ "हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने संस्थापक सर का मार्गदर्शन प्राप्त है। उनके सान्निध्य में कार्य करना हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।" इस अवसर पर अध्यक्ष श्री एस. के. डी. सिंह सर ने भी सभी को संबोधित करते हुए विद्यालय परिवार के समर्पण और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, "मैं आप सभी के प्रयासों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमें सदैव एकजुट रहकर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप सबका प्रेम और समर्पण ही एसकेडी परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है।" उन्होंने सभी को आशीर्वाद देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। चेयरमैन सर ने एस.के.डी. इंटरनेशनल स्कूल के नए लॉन्च पर भी सभी को बधाई दी और विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य हेतु अपने आशीर्वाद प्रदान किए। एस.के.डी. परिवार की ओर से चेयरमैन श्री एस. के. डी. सिंह सर को 81वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

संक्षिप्त खबरें

पंचकोसी परिक्रमा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर तैनात रहे सुरक्षा कर्मी

अयोध्या। शनिवार को पंच कोसी परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए जहां एक तरफ स्वयं कमिश्नर राजेश कुमार,आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे व एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर खुद भ्रमणशील रहे तथा इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं से हाल–चाल भी लेते हुए दिखाई दिए। यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से करने के लिए चारों तरफ पहले से ही तय की गई योजना के मुताबिक पुलिस प्रशासन द्वारा जगह–जगह पर बैरियर बैरिकेडिंग लगाए गए थे।खासकर उदय पब्लिक चौराहा, चूड़ामणि चौराहा, बेनीगंज चौराहा, भवदीय स्कूल के समीप, आईटीआई के सामने, लता मंगेशकर चौराहा, सहित कई प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर बैरियर बैरिकेडिंग लगे हुए थे।इन जगहों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे।उदय चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा, सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह सहित अन्य निरीक्षक तथा यातायात निरीक्षक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौजूद रहे। वही आईटीआई स्कूल के सामने बैरियर पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पांडे, थाना कैंट थानाध्यक्ष पंकज सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान बीच–बीच में इन पुलिसकर्मियों से वह स्थानीय लोग जो अयोध्या के निवासी थे और अंदर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा घूम कर जाने को कहा गया तो वे सभी विरोध करने लगे। लेकिन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पांडे ने उन्हें लोगों को वाहन सहित अंदर जाने दिया जिसके पास आधार कार्ड था।इसके अलावा दशरथ कुंड पर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश मौजूद रहे।

14 कोसी व पंचकोसी परिक्रमा मे एसपी ग्रामीण मे नजर आया सुरक्षा के साथ साथ मानवीय चेहरा

अयोध्या। चाहे 14 कोसी परिक्रमा हो या फिर पंचकोसी परिक्रमा जहां एक ओर विभिन्न संगठनों द्वारा संस्थाओं द्वारा परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भावना से सेवा करने में दिखाई दे रहे थे।वही पुलिस जहाँ इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जुटी रही वही उनके अंदर मानवता भी साफ–साफ नजर आ रही थी।जी हम बात कर रहे हैं एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी की।जो अभी 14 कोसी परिक्रमा में इन्होंने ऐसे ऐसे दिव्यांगों,कमजोर तथा चलने में असमर्थ परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को व्हीलचेयर तथा उनको किसी तरीके से सडक पार कर कर उनकी मदद किया।वही पंचकोसी परिक्रमा में भी जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए स्वयं तथा पुलिसकर्मियों को भी सख्त निर्देश देते हुए दिखाई दिए।कहा कि हम सभी ऐसा कार्य करें कि यहाँ पर आये श्रद्धालु सिर्फ पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा ही नहीं बल्कि हमशश द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की भी चर्चा दूर–दूर तक करें। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान उन्होंने जहां ए ऐसे श्रद्धालु जो चलने में कठिनाई महसूस कर रहे थे उनको तो सहायता प्रदान ही किया साथ ही साथ उनकी मानवता उस समय दिखाई दिया जब एक बच्चा सड़क के बीचो–बीच खोमचा लगाकर नमकीन आदि बेच रहा था तभी उन्होंने उसे अपने पुलिसकर्मियों की मदद से उसे खोमचे को सड़क के किनारे कराया।उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता परिक्रमा के दौरान जहां एक ओर अराजक तत्वों से निपटना है,इसके अलावा हम सब की निगाह परिक्रमा कर रहे सभी श्रद्धालुओं चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, के अलावा ऐसे दुकानदार जो कि सड़क के किनारे हो उनकी मजबूरी को भी देखें और उनकी मदद करें।

परिक्रमा के दौरान बेहोश हुए श्र)ालु को पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाने पर रही सराहनीय भूमिका

अयोध्या। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान जहां एक तरफ सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा को लेकर तत्पर रहे वही पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर उस समय दिखाई दिया। जब परिक्रमा कर रहे 60 वर्षीय श्रद्धालु दशरथ कुंड के पास बेहोश होकर गिर पड़ा।तभी वहां पर तैनात थानाध्यक्ष कुमारगंज ओमप्रकाश ने उन्हें उठाकर किनारे किया और पानी पिलाते हुए तत्काल एंबुलेंस को सूचना दिया।सूचना पाते ही थोड़ी ही देर में एंबुलेंस आई और उक्त श्रद्धालु को श्री राम चिकित्सालय पहुंचाया।जिसके चलते उसकी जान बची।इस संबंध में थानाध्यक्ष कुमारगंज ओमप्रकाश ने बताया कि बेहोश हुए श्रद्धालु की पहचान नवमी लाल उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ऐरा खमरिया जनपद लखीमपुर खीरी के रुप मे हुई है।जो परिक्रमा करते समय दशरथ कुंड के पास आज सुबह 08.00 बजे चक्कर खाकर गिर गया था।जिनको तत्काल एंबुलेंस बुलाकर श्रीराम हॉस्पिटल भेजा गया।उनके द्वारा किये गये इस सराहनीय कार्य व सहयोग का परिवार वालों ने प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।

संक्षिप्त खबरें

नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन

अयोध्या।शनिवार को भोर से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा करते हुए राम धुन तथा राम–राम करते हुए पुण्य के भागीदार बनते हुए दिखाई दे रहे थे। वही इस दौरान परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सेवा कर कर परोपकार करने में जुटे हुए थे।इस मौके पर शहर के समाजसेवी तथा चिकित्सक

डाक्टर तपन चौधरी,डॉक्टर कृतांत सिंह ने चूड़ामणि चौराहे पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हुए थे।इस मौके पर निस्वार्थ की भावना से कई चोटिल परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा भाव से इलाज व दवा वितरित करते हुए नजर आए।

24 घटे में 10 मिमी हुई बारिश

भदोही, (संवाददाता)। बंगाल की खाड़ी में उठे मोंथा चक्रवात का असर जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में बुधवार की रात से रुक–रुककर हो रही बारिश बृहस्पतिवार को भी जा रही। मौसम विभाग के अनुसार, 24 घंटे में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञा ने बारिश से 20 फीसदी फसल प्रभावित होने की आशंका जताई है। चौथे दिन भी सूर्य बादलों में ही छिपे रहे। तेज हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। खेतों में पककर खड़ी धान की फसल गिर गई है। बारिश के कारण खेतों में काटकर छोड़ी गई धान की फसल भींग गई। शहर से लेकर गांव तक सड़कों पर कीचड़ फैल गया है। मोंथा चक्रवात के कारण बुधवार शाम को शुरु हुई रिमझिम बारिश बृहस्पतिवार शाम तक जा रही। बारिश के कारण किसान चिंतित है। कई जगहों पर धान की बालियां मिट्टी में लग गई हैं। विशेषज्ञों का कहना कि यदि यह स्थिति दो–तीन दिन और बनी रही तो धान की फसल पूरी तरह खराब हो सकती है। बारिश से तापमान में मात्र एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल ने बताया कि बृहस्पतिवार को दिन का तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया जबकि रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। उन्होंने शुक्रवार को भी बूंदाबांदी की संभावना जताई है। जिला प्रशासन से किया मुआवजे की मांग रू डीघ ब्लॉक के किसान कल्लू मिश्रा, दीनानाथ तिवारी, सुरेश मिश्रा और रामराज यादव ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से मुआवजे की मांग की है। कहा फसलें खराब होती हैं तो किसानों को उचित क्षतिपूर्ति और मुआवजा प्रदान किया जाए। खाद, बीज और डीजल की महंगाई से लागत बढ़ चुकी है, ऐसे में फसल खराब होने से उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी।

वरदान चेरिटेबल ट्रस्ट की बैठक में आगामी विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा तय

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

वरदान चौरिटेबल ट्रस्ट की गांधी भवन में ट्रस्टी तथा सहयोगियों की एक बैठक वरिष्ठ ट्रस्टी अरुणेश बाजपेई की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्थापक प्रबन्ध न्यासी ए. के. चतुर्वेदी के जन्मोत्सव पर 14 नवम्बर को आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी तथा अंतिम रूप दिया गया।ज्ञात हो कि पुण्यात्मा श्री चतुर्वेदी की स्मृति में दस हजार की धनराशि किसी एक को हाई स्कूल में दिव्यांग छात्र/ छात्रा को उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले को दी जाती है तथा स्मृति चिन्ह दिया जाता है इस वर्ष वेणी माधव की छात्रा कुमारी वैष्णवी तिवारी को दिया जाएगा। इसके अतरिक्त पुण्यात्मा शोभना चतुर्वेदी की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों में हरदोई का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस हेतु संगीत के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर नाम रोशन करने वाली अनुषा त्रिवेदी, खेलकूद के क्षेत्र में पारुल यादव को राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक प्राप्त करने तथा दीक्षा द्विवेदी को शिक्षा के क्षेत्र में नीट में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया जाएगा।इसके अतिरिक्त सौरभ पटेल ग्राम पडरा लखनपुर माधोगंज को आई. ए. एस में चयनित होने पर विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

30 नवंबर को घण्टाघर प्रांगण में होने वाले सामूहिक विवाह एवं निकाह समारोह हेतु दिनांक 16 नवम्बर को दिन के दस बजे से वर वधुओं का साक्षात्कार गांधी भवन प्रांगण में होगा साक्षात्कार हेतु गिरीश मिश्रा एडवोकेट, अविनाश गुप्ता पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता श्रवण दीक्षित एडवोकेट, उमाकांत एडवोकेट तथा आलोकिता श्रीवास्तव, रूपाली,सरिता अग्रवाल व चेतना शुक्ला की टीम गठित कर दी गई है।

यह जानकारी देते हुए ट्रस्ट के सचिव अतुल कांत द्विवेदी न यह भी बताया कि 14 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में गुरु गोरखनाथ विद्यालय में बाल मेले का भी आयोजन किया जाएगा उपरोक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अमित कुमार घोष आई. ए.एस. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन रहेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट के गठन के समय इक्यावन विवाह कराए जाने का निर्णय लिया गया था। विगत तीन वर्षो से पुण्यात्मा चतुर्वेदी की पुत्री ट्रस्टीपल्लवी के द्वारा ट्रस्ट के बैनर तले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामूहिक विवाह सम्पन्न कराए जा रहे है।

बैठक के दौरान वर्चुअली वर्तमान प्रबन्ध न्यासी भुवन चतुर्वेदी उपस्थित रहे।

बैठक में ट्रस्टी अतुल कपूर ट्रस्टी करुणा शंकर द्विवेदी,श्रवण मिश्रा, आशीष, मनीष मिश्रा, जगिंदर सिंह, गांधी, अनुराग मिश्रा, सुयश बाजपेई, राकेश, अनिल श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, अविनाश मिश्रा, प्रेम शुक्ला, सत्यम मिश्रा शुभम मिश्रा उपस्थित रहे।

मोंथा के असर से गोरखपुर में पांच डिग्री गिरा पारा, लोगों ने निकाले स्वेटर

गोरखपुर, (संवाददाता)। मोंथा तूफान के प्रभाव से बृहस्पतिवार को गोरखपुर समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिनभर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में लगभग 10 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि करीब 22 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से पुरवा हवा चली। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा। सामान्य से 8.7 डिग्री की यह कमी अक्तूबर महीने के लिहाज से असामान्य मानी जा रही है। आम तौर पर अक्तूबर में गोरखपुर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है लेकिन बृहस्पतिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच सिर्फ 1.7 डिग्री का अंतर रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, तापमान में ऐसी गिरावट आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलती है, जब घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप होता है। इस अप्रत्याशित ठंड से लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। कई जगह बच्चों और बुजुर्गों को स्वेटर और हल्के जैकेट पहने देखा गया। आंकड़ों के अनुसार, पिछले 13 वर्षों में अक्तूबर में गोरखपुर का अधिकतम तापमान कभी 31 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया था। इस बार 22.7 डिग्री तक पहुंचना एक नया रिकॉर्ड है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि अक्तूबर में तापमान सामान्यतः 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन ने न केवल लोगों को चौंकाया बल्कि किसानों के लिए भी नई चिंता खड़ी कर दी है। तेज हवा और बारिश से खेतों में खड़ी सब्जियों और धान की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मोंथा तूफान का प्रभाव अगले 24 घंटे तक बना रह सकता है। इसके बाद मौसम धीरे–धीरे साफ होगा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। मोंथा तूफान के चलते बृहस्पतिवार को पूर्वांचल में बारिश व तापमान में गिरावट का अनुमान था। इस वक्त अरब सागर की तरफ से भी नमी आ रही है, जिसके चलते तापमान में अप्रत्याशित उतार–चढ़ाव है। शुक्रवार को मोंथा तूफान का असर कम हो जाएगा। हालांकि दिन में कहीं–कहीं हल्की बारिश व बादलों की आवाजाही रहेगी। इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी।

अक्षय नवमी पर किया आंवले के वृक्ष का किया पूजन

भदोही, (संवाददाता)। जिले में अक्षय नवमी का पर्व बृहस्पतिवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। लोगों ने विधि विधान से आंवला के वृक्ष का पूजन किया। वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर प्रसाद ग्रहण किया। ज्ञानपुर, भदोही, सुरियावां, गोपीगंज, चौरी, औराई आदि स्थानों पर आंवला वृक्ष की पूजा की गई। शाम को लोग परिवार के साथ वृक्ष के नीचे भोजन ग्रहण किया। भिदिऊरा गांव निवासी आचार्य गणेश पांडेय ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी या कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तीन साल लगातार अक्षय नवमी का व्रत उपवास एवं पूजा करने से फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण, विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक
देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।